हिन्दी साप्ताहिक

RN I NO. UPHIN/2019/78747

वॉयस ऑफ कैपिटल

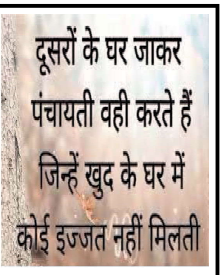

वर्ष– 06 अंक – 25 | लखनऊ, शुक्रवार 07 फरवरी 2025 | मूल्य–1 रूपया | पृष्ठ–8

संक्षिप्त समाचार

जम्मू–कश्मीर में सुरक्षा बलों ने ट्रक पर की ताबड़तोड़ Firing

एजेंसी

जम्मू। जम्मू–कश्मीर के बारामूला जिले में एक ऐसी घटना सामने आई है, जिसमें सुरक्षा बलों को एक ट्रक को रोकने के लिए गोली चलानी पड़ी, जिसके परिणामस्वरूप ट्रक के चालक की मौत हो गई। यह घटना तब घटी जब सुरक्षा बलों ने एक मोबाइल वाहन जांच चौकी (एमवीसीपी) पर संदिग्ध ट्रक को रुकने का संकेत दिया, लेकिन चालक ने रुकने के बजाय अपनी गति बढ़ा दी। सुरक्षा बलों ने ट्रक का पीछा किया और लगभग 23 किलोमीटर तक उसे रोकने का प्रयास किया। जब ट्रक ने भागने का प्रयास किया, तो सुरक्षा बलों ने उसके टायरों पर गोली मारी, जिससे ट्रक संग्राम चौक पर रुक गया। उस दौरान चालक भी गोली लगने से घायल हो गया। हालात के अनुसार, घायल चालक को तुरंत जीएमसी बारामूला अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को झटका

एजेंसी

पटना। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह को पटना सिविल कोर्ट के विशेष अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि यह मामला 22 जनवरी का है जब बाढ़ के पंचमहल थाना क्षेत्र के नौरंगा गांव में अनंत सिंह के समर्थकों और कुख्यात सोनू–मोनू गिरोह के सदस्यों के बीच दर्जनों राउंड गोलियां चलाई गई थीं। इस घटना के बाद दोनों पक्षों ने पंचमहल थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

भारतीयों की वापसी पर जयशंकर के बयान की युवा कांग्रेस ने की निंदा

एजेंसी

चंडीगढ़। अमेरिका से अप्रवासी भारतीयों की वापसी पर मचे हंगामे के बीच विदेश मंत्री एस. जयशंकर के इस बयान कि 'यह कोई नई प्रक्रिया नहीं है' की चंडीगढ़ युवा कांग्रेस ने कड़ी निंदा की है। गुरुवार को यहाँ जारी बयान में चंडीगढ़ युवा कांग्रेस के अध्यक्ष दीपक लुबना और महासचिव सुनील यादव ने कहा कि जिस तरीके से 104 अप्रवासियों को लाया गया, वह तरीका गलत था। उन्हें अपमानित किया गया।

'कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता', इमरजेंसी का जिक्र कर मोदी बोले- सत्ता सुख और शाही परिवार के...

एजेंसी

नयी दिल्ली। संविदान को लेकर जारी सियासत के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस पर जमकर वार किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपना संबोधन देते हुए मोदी ने कहा कि हम आगे बढ़ते हुए अपने संविधान निर्माताओं से प्रेरणा ले रहे हैं। जो लोग समान नागरिक संहिता पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह समझने की जरूरत है कि हम केवल अपने संविधान निर्माताओं की राह पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद हमारे संविधान निर्माताओं के कार्यों और भावनाओं को नष्ट कर दिया था। स्वतंत्रता के बाद एक स्टॉप–गैप व्यवस्था के दौरान हमारे संविधान के लोकाचार का अपमान करते हुए, एक ऐसी सरकार द्वारा संशोधन किए गए थे जिसे देश के लोगों द्वारा नहीं चुना गया था। मोदी ने कहा कि संविधान निर्माताओं का आदर करना चाहिए था, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए थी। लेकिन, कांग्रेस ने आजादी के तुरंत बाद ही संविधान निर्माताओं की भावनाओं की धज्जियां उड़ा दी थी। उन्होंने कहा कि

आजादी के बाद जब देश में चुनी हुई सरकार नहीं थी और चुनाव तक के लिए stop-gap arrangement था, तो उस stop-gap arrangement में जो महाशय बैठे थे, उन्होंने आते ही संविधान में संशोधन कर दिया। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कुचल दिया, अखबारों पर, प्रेस पर लगाम लगा दी। ये संविधान की भावना का पूरी तरह अनादर था। उन्होंने कहा कि इस देश ने इमरजेंसी का दौर भी देखा है। संविधान को किस प्रकार कुचला गया, संविधान की स्पिरिट को सत्ता सुख के लिए किस प्रकार रौंदा गया था, ये देश जानता है। इमरजेंसी में प्रसिद्ध सिनेमा कलाकार देव आनंद जी से कहा गया कि वे सार्वजनिक रूप से इमरजेंसी का समर्थन करें। लेकिन देव आनंद जी ने इसके लिए इंकार कर दिया। इसलिए दूरदर्शन पर देव आनंद जी की सभी फिल्मों को प्रतिबंधित कर दिया गया। किशोर कुमार जी ने कांग्रेस के लिए गाना गाने से मना किया। इस एक गुनाह के लिए आकाशवाणी पर किशोर कुमार के सभी गानों को प्रतिबंधित कर दिया गया। मोदी ने कहा कि आपातकाल में जॉर्ज फर्नांडिस समेत देश के अनेक महानुभावों को हथकड़ियां पहनाई गई थी, जंजीरों से बांधा गया था। संसद के सदस्य, देश के गणमान्य नेताओं को हथकड़ियों और जंजीरों से बांधा गया था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के मुंह से संविधान शब्द शोभा नहीं देता।

राजद की घोषणा छलावा, कभी पूरा नहीं होने वाला है : प्रशांत किशोर

एजेंसी

पटना। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने गुरुवार को बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल (राजद) पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि राजद की श्माई–बहिन मान योजनाश की घोषणा सिर्फ छलावा है। यह घोषणा कभी पूरी नहीं हो सकती। जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर ने गुरुवार को सत्याग्रह आश्रम में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि हम दूसरी पार्टियों की तरह नहीं हैं, जो कहते तो सब कुछ हैं, लेकिन करते कुछ नहीं हैं।

जारी होंगे वोटिंग के आंकड़े, फॉर्म 17 सी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

एजेंसी

नयी दिल्ली। दिल्ली चुनाव की वोटिंग पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई। ये याचिका फॉर्म 17सी को लेकर है। इसमें कोर्ट से चुनाव आयोग को आदेश देने की मांग की गई है कि वोटिंग के बाद के आंकड़े पब्लिक डोमेन पर अपलोड किए जाएं। जिससे चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बरकरार रहे। 5 फरवरी को शाम 6 बजे दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग पूरी हो गई लेकिन वोटिंग पूरी होते ही सुप्रीम कोर्ट में फॉर्म 17सी को लेकर एक पीआईएल दाखिल की गई। याचिका में चुनाव आयोग को

वोटिंग खत्म होने के तुरंत बाद फॉर्म–17सी वेबसाइट पर डालने का आदेश देने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि फॉर्म 17सी की सार्वजनिक तौर पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को तुरंत इसे वेबसाइट पर डालने का आदेश दिया जाना चाहिए.. इससे चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और चुनावी अनियमितताओं पर रोक लगेगी।

यूजीसी मसौदा नियमों पर राहुल गांधी ने किया हमला, कहा-देश की विविधता का सम्मान होना चाहिए

एजेंसी

नयी दिल्ली। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के मसौदा नियमों का हवाला देते हुए बृहस्पतिवार को आरोप लगाया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) का इरादा देश पर एक विचार, एक इतिहास और एक भाषा थोपने का है, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा। वह यूजसी के मसैदा नियमों के खिलाफ यहां जंतर मंतर पर द्रमुक की छात्र इकाई द्वारा आयोजित प्रदर्शन में शामिल हुए। राहुल गांधी ने दावा किया, ''आरएसएस का उद्देश्य अन्य सभी इतिहास, संस्कृतियों और परंपराओं को मिटाना है। यही तो वे हासिल करना चाहते हैं। उनका इरादा देश पर एक ही विचार, इतिहास और भाषा थोपने का है। उन्होंने आरोप

लगाया कि आरएसएस विभिन्न राज्यों की शिक्षा प्रणालियों के साथ भी ऐसा ही करने का प्रयास कर रहा है तथा यह उनके एजेंडे को आगे बढ़ाने का एक और कदम है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा, ''प्रत्येक राज्य की अपनी अनूठी परंपरा, इतिहास और भाषा होती है, यही कारण है कि संविधान में भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है। हमें इन मतभेदों का सम्मान करना चाहिए और समझना चाहिए। उनके मुताबिक, तमिल लोगों का हजारों वर्षों से चला आ रहा समृद्ध इतिहास, संस्कृति और परंपरा है। राहुल गांधी ने कहा, ''यह तमिल लोगों और अन्य राज्यों का अपमान है जहां आरएसएस अपनी विचारधारा थोपने की कोशिश कर रही है। यह आरएसएस द्वारा उन सभी चीजों को कमजोर करने का एक प्रयास है। उनका कहना था, ''कांग्रेस पार्टी और 'इंडिया गठबंधन में बहुत स्पष्ट है कि हर एक राज्य, हर इतिहास, हर भाषा और हर परंपरा का सम्मान किया जाना चाहिए। उनके साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, अलग–अलग नहीं। राहुल गांधी ने कहा, ''हमने अपने घोषणापत्र में पहले ही कहा था कि शिक्षा को राज्य सूची में वापस लाया जाएगा।

सम्पादकीय

लोकतंत्र को निगलता पूंजीवाद

भापने दूसरे कार्यकाल में कुछ और ज्यादा दबंग होकर शासन करने की मंशा पाले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब बेहद खतरनाक खेल खेलने पर उतारू हो गए हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका के पहले विदेशी मेहमान बने। इस बात से ही जाहिर हो जाता है कि अमेरिका और इजरायल के बीच किस किस्म की घनिष्ठता है। नेतन्याहू से मुलाकात के बाद एक प्रेस कांफ्रेंस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर अमेरिका के नियंत्रण से जुड़ा चौंकाने वाला प्रस्ताव पेश किया। ट्रंप का मानना है कि गजा एक ऐसी जगह है जहां सब कुछ ध्वस्त हो चुका है। अब अमेरिका गजा पट्टी को नियंत्रण में लेकर यहां से जिंदा बमों को हटाकर, पुनर्निर्माण करके अर्थव्यवस्था को गति देने का काम कर सकता है। बकौल ट्रंप फिलीस्तीन के लोग केवल इसलिए गजा वापस जाना चाहते हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। इसलिए ट्रंप ने प्रेस कांफ्रेंस में कहा कि गजा के 18 लाख लोगों को दूसरे अरब देशों में भेज देना चाहिए, ताकि अमेरिका गजा पर नियंत्रण करे और इस बर्बाद हो चुके फिलीस्तीनी क्षेत्र को फिर से बनाए। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या उनके इस ताजा रुख के मायने ये हैं कि वो इजरायल और फिलीस्तीन के विवाद को सुलझाने के लिए दो राष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ हैं। तो ट्रंप ने जवाब दिया, इसका दो राष्ट्र या एक राष्ट्र या किसी भी राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। गनीमत है कि जवाब देने में ट्रंप ने ईमानदारी दिखाई कि इसका किसी भी राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है। वैसे भी ट्रंप इस समय जो कर रहे हैं, वही अमेरिका की मंशा हमेशा से रही है। फर्क यही है कि अब तक के राष्ट्रपतियों ने खुलकर गजा पर अधिकार जमाने की बात नहीं की थी, ट्रंप विकास, रोजगार और पुनर्निर्माण जैसे शब्दों की जुगाली करते हुए इस बात को बेझिझक कह रहे हैं। ट्रंप ने गजा पट्टी की तुलना नरक से करते हुए कहा, श्यहां लोगों को कभी जीने का मौका नहीं मिला।श हालांकि उनसे पूछा जाना चाहिए कि गजा को नरक बनाने में अमेरिका की भूमिका के बारे में वे क्या कहेंगे। यहूदियों को बसाने के लिए इजरायल नाम के नए देश का निर्माण आखिर किस की पहल पर हुआ। ट्रंप अब भी गजा के लोगों को दूसरे अरब देशों में भेजने की बात कर रहे हैं, अगर उन्हें भलाई करने का इतना ही शौक है तो क्यों नहीं अमेरिका में उन्हें बसने बुला लेते। अभी तो वे अमेरिका से उन लोगों को भी खदेड़ रहे हैं, जिनके पास अमेरिकी कानून के तहत पूरे कागजात नहीं हैं। ऐसे प्रवासी अवैध कहे जा सकते हैं, लेकिन ट्रंप तो इन्हें अपराधियों की तरह हथकड़ी लगाकर वापस भेज रहे हैं। भारत में भी बुधवार को ऐसे प्रवासी भारतीयों की पहली खेप आई है। वैश्विक स्तर पर यह देश का बड़ा अपमान है। अफसोस की बात यह है कि इतनी बड़ी शर्मिंदगी का अहसास प्रधानमंत्री को नहीं है, वे गंगाजी में डुबकी लगाने का आनंद ले रहे हैं। बहरहाल, गजा पर ट्रंप की योजना पर उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में गजा पर अमेरिका का स्वामित्व होगा, क्या आप किसी संप्रभु क्षेत्र पर कब्जा करने की बात कर रहे हैं? तो ट्रंप ने कहा, हां. वह अमेरिका की अगुवाई में लंबे समय तक ऐसा नियंत्रण करने की कल्पना कर रहे हैं। उस जमीन के टुकड़े पर अधिकार पाना, उसका विकास करना, हजारों नौकरियां पैदा करना। ये वाकई शानदार होगा। हर कोई इस विचार को पसंद करता है। इस हर कोई में कौन–कौन शामिल है, इसका खुलासा तो अभी नहीं हुआ है, लेकिन मिस्र, जॉर्डन, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, फिलीस्तीनी प्राधिकरण और अरब लीग ने एक साझा बयान जारी करते हुए ट्रंप की इस योजना को खारिज और चेतावनी दी है कि इस तरह की योजना क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा पैदा करेंगी और संघर्ष तेज होने का जोखिम भी बढ़ाएगी। हमास भी स्वाभाविक तौर पर इस योजना से नाराज है। गौरतलब है कि अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत किसी जगह की आबादी को जबरन कहीं और भेजना प्रतिबंधित है। लेकिन ट्रंप खुलेआम इस कानून की धज्जियां उड़ाने की योजना बता रहे हैं। अरब देश इसकी मुखालफत भले ही कर लें, लेकिन क्या ट्रंप को इस योजना पर अमल करने से रोका जा सकेगा, यह बड़ा सवाल है। क्योंकि ट्रंप के इर्द–गिर्द इस समय जो लोग खड़े हैं, उनके लिए मुनाफा ही सबसे बड़ा धर्म है और इसमें इंसानियत जैसे शब्दों की कोई जगह नहीं है। गजा को स्वर्ग बनाने के पीछे किस तरह भू राजनैतिक स्थितियों से छेड़छाड़ होगी, इजरायल और अमेरिका की खुफिया एजेंसियां, सेनाएं और तकनीकी ताकतें किस तरह के दुष्चक्र रचेंगी, इनका अंदाजा भी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता। हालांकि ट्रंप के एक और फैसले से इस खेल की चालाकी समझी जा सकती है। टेस्ला कंपनी के मालिक, दुनिया के सर्वाधिक अमीर कारोबारियों में से एक और इस समय ट्रंप के सबसे करीबी माने जाने वाले एलन मस्क की पहुंच अब अमेरिकी सरकार की भुगतान प्रणाली तक हो गई है। मस्क द्वारा संचालित डीओजीई यानी सरकारी दक्षता विभाग को सामाजिक सुरक्षा और मेडिकेयर ग्राहक भुगतान प्रणालियों सहित संवेदनशील वित्तीय डेटा तक पहुंच मिल गई है। डीओजीआई को लेकर पहले ही अमेरिका में संदेह व्यक्त किया जा रहा है। ट्रम्प प्रशासन ने इस टास्क फोर्स का गठन ही इसलिए किया है ताकि संघीय कर्मचारियों को नौकरी से निकालने, कार्यक्रमों में कटौती करने और संघीय नियमों को कम करने के तरीके खोजे जा सकें। आसान शब्दों में कहें तो सरकार अपनी जिम्मेदारी इस टास्क फोर्स के जरिए कम करना चाहती है। इसकी कमान एलन मस्क के हाथों में है, जो विशुद्ध कारोबारी हैं और जिन्हें सरकार के संचालन में हिस्सा लेने के लिए अमेरिकी जनता ने निर्वाचित नहीं किया। अमेरिकी जनता ने डोनाल्ड ट्रंप को राष्ट्रपति चुना है। लेकिन ट्रंप बेहतर प्रशासन के नाम पर कारोबारियों को बढ़ावा दे रहे हैं। अमेरिकी ट्रेजरी तक मस्क की पहुंच इसका बड़ा प्रमाण है। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई सांसद इस बात से काफी परेशान हैं कि मस्क के पास अमेरिकी सरकार में बहुत अधिक शक्ति है, उन्हें डर है कि मस्क के लोग अपने राजनीतिक एजेंडे के अनुरूप भुगतान को अवैध रूप से रोक सकते हैं।

बजट 2025-26 में भारी कर छूट का मोदी का दांव क्यों विफल होगा?

नित्य चक्रवर्ती

2025–26 के केन्द्रीय बजट को संसद में पेश किये जाने के बाद देश के आयकरदाताओं को भारी राहत दिये जाने पर भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के मंत्रियों में जो उत्साह है, उसमें देश के उन अनुमानित एक करोड़ लोगों का भी योगदान हो सकता है, जिन्हें बजट प्रस्तावों से लाभ मिला है। लेकिन लोगों के उपभोक्ता व्यवहार पर इसका प्रभाव सीमित होगा और उतना बड़ा नहीं होगा, जितना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित नीति निर्माता उनके होने का अनुमान लगा रहे हैं। 2025–26 के बजट के दो कार्य हैं, जो नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। पहला, खपत को बढ़ावा देना, क्योंकि चालू वित्त वर्ष में खपत सुस्त रही है और दूसरा, युवाओं के लिए नौकरियों का तेजी से सृजन करना, क्योंकि बेरोजगारी चरम संकट बिंदु पर पहुंच गयी है। इन दोनों मामलों में, 2025–26 के बजट प्रस्तावों में कोई उम्मीद की किरण नहीं है। बजट निर्माताओं, खासकर प्रधानमंत्री में,भारी सुधार लाने की हिम्मत गायब है, हालांकि इसके लिए यह सबसे अच्छा समय था क्योंकि लोकसभा चुनाव चार साल दूर हैं। सत्तारूढ़ सरकार को अपने अस्तित्व के लिए तत्काल कोई खतरा नहीं है। भाजपा नेतृत्व वाली सरकार ने अर्थव्यवस्था में खपत और उसके परिणामस्वरूप मांग को बढ़ावा देने के लिए आधा–अधूरा दृष्टिकोण अपनाया और रोजगार सृजन के कार्य को पूरी तरह से छोड़ दिया। इसका कुल प्रभाव यह होगा कि कुछ क्षेत्रों में खपत में वृद्धि की कुछ लहरें उठेंगी, लेकिन एक लाख करोड़ की कुल कर राहत, मांग चक्र को गति देने में सक्षम नहीं होगी क्योंकि ग्रामीण और शहरी गरीबों की खराब खर्च क्षमता सहित अन्य कारक स्थिर रहेंगे, जिससे खपत में सामान्य उछाल की प्रक्रिया पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आयकरदाताओं को एक लाख करोड़ रुपये की राहत के बारे में वास्तविकता पर नजर डालते हैं। 2023–24 के आर्थिक सर्वेक्षण में सामने आये आंकड़ों के अनुसार, वेतनभोगियों में, 2023–24 में पुरुष श्रमिकों के लिए वास्तविक औसत मासिक वेतन 2017–18 में 12,665 रुपये से 6.4 प्रतिशत कम होकर 11,858 रुपये था। महिला श्रमिकों के लिए, इस अवधि के दौरान वास्तविक मजदूरी में और अधिक गिरावट आई। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेतनभोगी लोगों के एक बड़े हिस्से, विशेष रूप से निचले और मध्यम वर्ग को कुछ आवश्यक सामान प्राप्त करने के मामले में भी बदतर जीवन स्थितियों का सामना करना पड़ा। यह वर्ग नये सामान खरीदने नहीं जायेगा, बल्कि इस अवधि में छूटी हुई कुछ जरूरी चीजें वापस पाने की कोशिश करेगा। पिछले दस वर्षों में मोदी सरकार की नीतियों का सबसे ज्यादा फायदा कॉरपोरेट सेक्टर को हुआ है। यह प्रक्रिया पिछले पांच वर्षों में ज्यादा स्पष्ट हुई। 2023–24 में मुनाफे में 22.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, लेकिन रोजगार में महज1.5 फीसदी की बढ़ोतरी हुई। 2024–25 में व्यक्तिगत कर संग्रह में पिछले वर्ष की तुलना में 19 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जबकि कॉर्पोरेट कर के मामले में यह वृद्धि केवल 7 प्रतिशत रही। इसका मतलब यह है कि मध्यम वर्ग के आयकरदाता कॉर्पोरेट क्षेत्र की तुलना में सरकार के कर राजस्व में अधिक योगदान दे रहे हैं, जिसे नरेंद्र मोदी शासन के दौरान सबसे अधिक लाभ हुआ है। 2025–26 के बजट में रोजगार पहल के संबंध में, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर नवीनतम रिपोर्ट कुल मिलाकर बिल्कुल भी आशाजनक नहीं है, हालांकि कुछ क्षेत्रों में परिणाम उत्साहजनक रहे हैं। दिसंबर 2024 में सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट में बेरोजगारी का प्रतिशत 7.8प्रतिशत बताया गया है। भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 में उल्लेख किया गया है कि आकस्मिक श्रमिक, जो कार्यबल का 25प्रतिशत हिस्सा हैं, उन्हें लगभग 4,712 रुपये मासिक वेतन मिलता है। स्व–नियोजित श्रेणी के लोग (जो कार्यबल का 42प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं) प्रति माह लगभग 6,843 रुपये कमाते हैं। कर राहत से मध्यम वर्ग (5 से 30 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले) और निम्न आय वाले परिवारों (2 से 5 लाख रुपये के बीच वार्षिक आय वाले) के बीच उपभोग संकट को कम करने में मदद मिल सकती है। वे उपभोक्ता बाजार में सतर्कता से खर्च करने वाले होंगे क्योंकि उनके पास पहले से ही शिक्षा और स्वास्थ्य की लागत सहित आवश्यकताओं की मांग है। इनमें से अधिकांश समूह कृषि क्षेत्र, स्व–स्वामित्व वाले व्यवसायों और एमएसएमई क्षेत्र में कार्यरत हैं। साथ में, वे भारत की कामकाजी आबादी का 70प्रतिशत हिस्सा बनाते हैं, जिसमें 40 करोड़ कम उत्पादक कृषि क्षेत्र और लगभग 25 करोड़ एमएसएमई क्षेत्र में फंसे हुए हैं। बढ़ती अर्थव्यवस्था में हाउसकीपिंग, सुरक्षा सेवाएं और अन्य गिग प्रकार की नौकरियों जैसे कम वेतन वाली और कम उत्पादक नौकरियों का सृजन भी हो रहा है। इस बजट में मोदी सरकार का पूरा दृष्टिकोण एक लाख करोड़ रुपये की राहत के तथाकथित गुणक प्रभाव पर आधारित है और यह अनुमान लगा रहा है कि पूरी राशि उपभोग के लिए खर्च की जायेगी, जो वास्तव में होने वाला नहीं है। अधिकतम 50,000 करोड़ रुपये कुल राशि का आधा हिस्सा नये उपभोग के लिए खर्च किया जा सकता है।

कैसे रुकें सिवरेज की सफाई में होने वाली मौत?

अशोक मधुप

कोलकाता शहर में सिवरेज की सफाई के दौरान तीन श्रमिकों की मौत हो गई। घटना कोलकता लेदर कंप्लेक्स में सीवरेज लाइन के साफ के दौरान हुई। सुप्रीम कोर्ट काफी पहले कह चुका है कि मरने वालों के परिवार को तीस.तीस लाख रूपया मुआवजा दिया जाए, किंतु ऐसा नहीं हो रहा। प्रदेश सरकार ने बीस.बीस लाख रूपये मुआवजा देकर ही मामला निपटा दिया। यह घटना सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के चार दिन बाद हुई है, जिस आदेश में सुप्रीम कार्ट ने कहा कि कि दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चिन्नई, बंगलूरू और हैदराबाद जैसे मैट्रोपालिटिन शहरों में मैनुअल सफाई और सीवर सफाई पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया था। दरअसल न्यायालय आदेश करता है किंतु उन आदेश के पालन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को या तो ये आदेश पंहुच नहीं पाता। आदेश पंहुच पाता है तो फाइलों के दबाव में वे उसे पढ़ नहीं पाते। इसीलिए बार–बार आदेशों के पालन में अनदेखी होती है। इन आदेशों को संबधित अधिकारियों तक पंहुचाने की प्रदेश स्तर पर त्वरित और प्रभावी व्यवस्था होनी चाहिए। जुलाई 2022 में लोकसभा में प्रस्तुत सरकारी आंकड़ों के अनुसार पांच साल में सीवर सफाई के दौरान 347 लोगों की मौत हुई। पांच सालों में भारत में सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कम से कम 347 लोगों की मौत हुई, जिनमें से 40 प्रतिशत मौतें उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और दिल्ली में हुईं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, 1993 के बाद से सीवर और सेप्टिक टैंक से होने वाली मौतों के 1,248 मामलों में से इस साल मार्च तक 1,116 मामलों में मुआवजे का भुगतान किया गया है, हालांकि, 81 मामलों में मुआवजे का भुगतान अभी भी लंबित है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि राज्यों द्वारा 51 मामले बंद कर दिए गए हैं क्योंकि मृत व्यक्तियों के कानूनी उत्तराधिकारी नहीं मिल सके। 1993 के बाद के आंकड़ा से पता चलता है कि कि सीवर और सेप्टिक टैंक में होने वाली मौतों के सबसे अधिक 256 मामले तमिलनाडु में सामने आए। इसके बाद गुजरात (204), उत्तर प्रदेश (131), हरियाणा (115) और दिल्ली (112) का नंबर आता है। सीवर से होने वाली मौतों के सबसे कम मामले छत्तीसगढ़ (1) में दर्ज किए गए हैं, इसके बाद त्रिपुरा और ओडिशा में 2–2 मामले, दादर और नगर हवेली (3) और झारखंड (4) आते हैं। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक के 58 मामलों में से सबसे ज्यादा मामले तमिलनाडु (11) से हैं, इसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान (11–11 मामले), और गुजरात (8) तथा पंजाब (6) का नंबर आता है। आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि 1993 के बाद से हुई 1,247 मौतों में से 456 मामले 2018 के बाद दर्ज किए गए हैं। नौ अक्तूबर 2024 को दिल्ली के सरोजिनी नगर इलाके में एक कंस्ट्रक्शन साइट पर तीन मजदूरों की मौत का मामला सामने आया है। ये मजदूर सीवर लाइन साफ करने के लिए सीवर के अंदर उतरे थे। सीवर लाइन से निकल रही जहरीली गैस की वजह से तीनों मजदूरों का दम घुट गया था। स्थानीय लोगों का कहना है कि सीवर में उतरे मजदूरों के लिए सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं थे। 23 अक्तूबर 2024 को राजस्थान के सीकर जिले में सफाई के दौरान तीन कर्मचारियों की मौत हो गई। ये मौत लगातार होती रहती है। रूक नही पातीं। देश में सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौत की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने 20 अक्टूबर 2023 को कहा था कि सरकारी अधिकारियों को मरने वालों के परिजन को 30 लाख रुपए मुआवजा देना होगा।सीवर की सफाई के दौरान कोई सफाईकर्मी स्थायी दिव्यांगता का शिकार होता है तो न्यूनतम मुआवजे के रूप में उसे 20 लाख रुपए दिया जाएगा। वहीं, अन्य दिव्यांगता पर अफसर उसे 10 लाख रुपए तक का भुगतान करेंगे। जस्टिस एस रवींद्र भट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने सीवर सफाई के दौरान होने वाली मौतों को लेकर दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान यह फैसला सुनाया।

यूपी में जल परिवहन और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, प्राधिकरण के गठन को कैबिनेट की मंजूरी

संवाददाता

लखनऊ। प्रदेश की योगी सरकार ने राज्य में जल परिवहन एवं जल पर्यटन को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के गठन को मंजूरी दे दी है। इस प्राधिकरण के कार्यों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए उत्तर प्रदेश जलमार्ग प्राधिकरण नियमावली 2025 को प्रख्यापित किया गया है। योगी कैबिनेट ने इस नियमावली को अपनी सहमति प्रदान कर दी है। गुरुवार को लोकभवन में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बैठक में 12 प्रस्तावों पर चर्चा हुई। इनमें से एक को छोड़कर 11 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। गौरतलब है कि देश में 111 राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किए गए हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश में गंगा, यमुना सहित कुल 11 राष्ट्रीय जलमार्ग मौजूद हैं। जलमार्गों के जरिए परिवहन को किफायती और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से इस प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। सरकार का मानना है कि जल परिवहन प्रणाली विकसित होने से यातायात के अन्य साधनों पर दबाव कम होगा और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। इस प्राधिकरण का नेतृत्व मुख्यमंत्री द्वारा नामित परिवहन मंत्री या अंतर्देशीय जलमार्ग, शिपिंग, नेविगेशन, पोर्ट्स और मैरीटाइम मामलों के विशेषज्ञ द्वारा किया जाएगा। उपाध्यक्ष के रूप में ऐसे ही विशेषज्ञ व्यक्तियों में से किसी एक को राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसके अलावा, वित्त, लोक निर्माण, पर्यटन एवं संस्कृति, सिंचाई एवं जल संसाधन और वन एवं पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव या प्रमुख सचिव इस प्राधिकरण के पदेन सदस्य होंगे। इसके अलावा, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के अध्यक्ष द्वारा नामित एक प्रतिनिधि भी सदस्य के रूप में शामिल होगा। उत्तर प्रदेश के परिवहन आयुक्त इस प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। इस प्राधिकरण के अंतर्गत विभिन्न महत्वपूर्ण प्रावधानों को शामिल किया गया है। इनमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य, आवासीय व्यवस्था, यात्रा भत्ता, बैठकों की प्रक्रिया, कोरम, सलाहकार समितियों का गठन, कार्य संचालन की प्रक्रिया, सदस्यों का कार्यकाल, विशेषज्ञों का पैनल, बजट, लेखा और लेखा परीक्षा से जुड़े नियमों को सम्मिलित किया गया

है। इसके अलावा, वार्षिक लेखा रिपोर्ट, आरक्षित निधि, तथा भूमि और संपत्ति में प्रवेश करने से संबंधित प्रावधान भी निर्धारित किए गए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार जल परिवहन के साथ–साथ जल पर्यटन को भी विकसित करने की योजना बना रही है। इस प्राधिकरण के माध्यम से विभिन्न पर्यटन स्थलों को जलमार्ग से जोड़ने और उन्हें आकर्षक बनाने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। इससे पर्यटकों को एक नया अनुभव मिलेगा और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम जल परिवहन को बढ़ावा देने और राज्य में आर्थिक विकास को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा। 2025–26 की आबकारी नीति को भी कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। लोक भवन में गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने बताया कि इस नीति के तहत शराब की दुकानों का लाइसेंस अब ई–लॉटरी द्वारा दिया जाएगा और इस बार पुराने लाइसेंस का रिन्यूवल नहीं किया जाएगा। हालांकि, 2026–27 में लाइसेंस रिन्यूवल का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा, सरकार ने 55 हजार करोड़ रुपये का राजस्व जुटाने का लक्ष्य तय किया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 4000 करोड़ रुपये अधिक है। नई नीति में यह भी प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति, फर्म या कंपनी दो से अधिक लाइसेंस नहीं ले सकेंगी। इसके अलावा, अब से विदेशी मदिरा 60 और 90 मिलीलीटर के पैक में भी उपलब्ध होगी, जो पहले नहीं थी। यूपी 112 के निर्बाध संचालन के लिए कैबिनेट ने 469 पुराने वाहनों की जगह 469 नए वाहनों का अनुमोदन प्रस्ताव मंजूर कर लिया। इसके लिए 43 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि खर्च की जाएगी। इसमें चार पहिया वाहनों के साथ–साथ दो पहिया वाहनों की भी खरीद की जाएगी।

शोभानाथ सिंह ग्यारहवी बार मुंशी संघ अध्यक्ष निर्वाचित

संवाददाता

लखनऊ। मुंशी संघ सिंचाई विभाग उत्तरप्रदेश का द्विवार्षिक अधिवेशन सचिवालय संघ के पूर्व अध्यक्ष हरिशरण मिश्रा और रोड़वेज कर्मचारी संघ के अध्यक्ष राकेश सिंह की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। चुनाव अधिकारी ड्राइंग एसोसिएशन के अध्यक्ष अमरजीत मिश्रा एवं अभय शुक्ला द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के उपरान्त नई कार्यकारिणी की घोषणा की गई। नई कार्याकारिणी में शोभानाथ सिंह (मनोज) ग्यारहवी बार मुंशी सघ के प्रदेश अध्यक्ष निर्वाचित घोषित किए गए। चुनाव अधिकारी ने बताया कि नव निर्वाचित कार्यकारिणी में प्रान्तीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष विकास कुमार त्यागी, उपाध्यक्ष अरुण खरे पूर्व ,उपाध्यक्ष पश्चिम शैलेन्द्र सिंह, प्रान्तीय महामंत्री धीरेन्द्र मिश्रा, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष वैद्यनाथ कुमार और प्रान्तीय सम्प्रेक्षक प्रवीणनाथ चुने गए। नव निर्वाचित कार्यकारिणी को मुख्य चुनाव अधिकारी अमरजीत मिश्रा ने शपथ दिलाई। संघ के अध्यक्ष शोभानाथ सिंह ने अपनी प्राथमिकता बताते हुए कहा कि मुंशी संघ नियमावली 1954 में प्रथम संशोधन करते हुए मुंशी संवर्ग हेतु त्रिस्तरीय प्रोन्नति की व्यवस्था, मुंशी पदनाम संशोधन, संवर्ग पुर्नगठन और तीन प्रान्नतियों, संवर्ग की वरिष्ठता सूची प्रदेशस्तरीय, शैक्षाणिक योग्यता स्नातक, डोयक सीसीसी प्रमाण, वेतनमान 29200–92300 लेवल–5 तथा हेडमुंशी का वेतनमान ग्रेड पे 4200 तथा संघ के लिए अन्य संघो की भाँति संघ भवन आवंटित किया जाए।

बेकाबू डंपर ने युवक–युवती को रौंदा, मौत

संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के गोमती नगर विस्तार में बेकाबू डंपर ने दो लोगों को रौंद दिया। बाइक सवार युवक–युवती गोमती नगर की तरफ से आ रहे थे। तभी तेज डंपर ने पीछे से टक्कर मार दी। राहगीरों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाघामऊ गोमतीनगर विस्तार की रहने वाली मीना राजपूत (18) पुत्री जगनू पत्रकार पुरम में साड़ी की दुकान में काम करती थीं। बुधवार रात करीब 10 बजे मलेसेमऊ के रहने वाले जोशीन के साथ वापस लौट रही थीं। तभी शालीमार वन वर्ल्ड के पास तेज रफ्तार डंपर ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर से दोनों उछल कर दूर जा गिरे और बुरी तरह घायल हो गए। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दोनों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल पहुंचाया। जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। गोमती नगर विस्तार इंस्पेक्टर सुधीर अवस्थी का कहना है कि डंपर शालीमार वन वर्ल्ड के निर्माण कार्य में लगा हुआ था। डंपर कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश की जा रही है। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भिजवा दिया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

दारुलशफा में नगर निगम और पुलिस ने सालों पुराने अवैध कब्जे को किया ध्वस्त

संवाददाता, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के दारुलशफा परिसर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू हो गई है। राज्य संपत्ति विभाग की टीम पुलिस और नगर निगम के साथ मिलकर सालों से चल रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर रही है। विधायक आवास परिसर में सड़क किनारे बनी 17 अस्थायी दुकानों और मकानों पर बुलडोजर चलाया गया। कार्यवाही के दौरान हजरतगंज पुलिस फोर्स और नगर निगम की टीम तैनात रही। राज्य संपत्ति अधिकारी के आदेश पर की जा रही इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि ये दुकानें और निर्माण लंबे समय से अवैध रूप से संचालित हो रहे थे।

बिजली विभाग में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर जताया आक्रोश

संवाददाता

लखनऊ। राजधानी लखनऊ में बिजली विभाग में तैनात आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने एमडी कार्यालय पर गुरुवार को प्रदर्शन किया है। मांगों को लेकर कार्यालय पर जुटे हजारों कर्मचारियों ने मध्यांचल प्रबंधन को कर्मचारियों की समस्याएं बताने के लिए सत्याग्रह का रास्ता चुना है। दरअसल, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के सहयोगी निगम, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड गोखले मार्ग लखनऊ के कार्यक्षेत्र में मानक से कम कर्मचारियों को तैनात कर कार्य कराने, पूर्व से तैनात कर्मचारियों की कुल संख्या के लगभग 40: भाग के बराबर कर्मचारियों की छटनी करने, 55 वर्ष का हवाला देकर कर्मचारियों को कार्य से हटाने, मध्यांचल प्रबंधन द्वारा पूर्व में हुए समझौते का पालन न करने, मानक के अनुरूप सुरक्षा उपकरण न देने, 8 घंटे 26 दिन के स्थान पर 12 घंटे 30 दिन कार्य कराने, कार्य के दौरान बिजली की चपेट में आने या खंभे से नीचे गिरकर घायल हुए कर्मचारियों का कैशलेस उपचार न कराने, उचित उपचार के अभाव में बड़े पैमाने पर कर्मचारियों की मृत्यु होने, दुर्घटना के शिकार कर्मचारियों द्वारा उपचार में

व्यय की गई धनराशि को संविदाकारों के बिल से काटकर भुगतान न करने, ईपीएफ घोटाले की जांच न कराने, 17 जनवरी 2025 को संगठन पदाधिकारियों व मध्यांचल प्रबंधन के बीच बनी सहमति के कार्यवृत्त में हेराफेरी करने के कारण आउटसोर्सिंग कर्मचारी एकजुट होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन निविदाध्संविदा कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय ने बताया है कि मध्यांचल प्रबंधन को बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं बताने के लिए संगठन ने प्रदर्शन करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत 5 फरवरी को मध्यांचल के अंतर्गत आने वाले जनपदों में विरोध सभा की है। वहीं आज यानी 6 फरवरी 2025 को प्रबंध निदेशक मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड कार्यालय पर कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है।

मिल्कीपुर उपचुनाव: सपा नेता प्रदीप यादव की गुमशुदगी पर बढ़ा बवाल

एसओ ने की थी अभद्रता, समाजवादी पार्टी ने दिया 24 घंटे का अल्टीमेटम

संवाददाता

लखनऊ। अयोध्या के मिल्कीपुर में समाजवादी पार्टी के नेता और जिला पंचायत सदस्य प्रदीप यादव की गुमशुदगी का मामला तूल पकड़ने लगा है। पुलिस को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 24 घंटे के अंदर उनकी वापसी नही होती है तो सपा विरोध प्रदर्शन करेगी।सपा ने आरोप लगाया कि प्रदीप यादव का एसओ देवेंद्र पांडे से विवाद हो गया था जिसके बाद से वो अब तक वापस नहीं लौटे। समाजवादी पार्टी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट कर पुलिस प्रशासन को विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। सपा ने लिखा,24 घंटे में यदि अयोध्या पुलिस ने प्रदीप यादव को सकुशल उनके घर नहीं भेजा तो समाजवादी पार्टी करेगी आंदोलन। उन्होंने लिखा मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिला पंचायत सदस्य के पति प्रदीप यादव से इनायतनगर थानाध्यक्ष देवेंद्र पांडे ने की थी अभद्रता, कहे थे अपशब्द, अत्यंत निंदनीय। तत्काल संज्ञान लें। सपा ने अपनी इस पोस्ट के साथ डीजीपी और अयोध्या पुलिस को भी टैग किया है। सपा का आरोप है कि मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान प्रदीप यादव का इनायत नगर के एसओ देवेंद्र पांडेय से विवाद हो गया था, जब देवेंद्र पांडेय ने उनके साथ अभद्रता और दुर्व्यवहार किया।सपा ने आरोप लगाया कि अब तक प्रदीप यादव अपने घर नहीं पहुँच पाए हैं। सपा ने अपनी पोस्ट के साथ प्रदीप यादव और उनके परिवार की तस्वीर भी शेयर की है।समाजवादी पार्टी की ओर से पुलिस प्रशासन को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर प्रदीप यादव अपने घर नहीं पहुंचे तो सपा के द्वारा पुलिस प्रशासन के खिलाफ आंदोलन किया जाएगा। मामले में पुलिस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई हैं। बुधवार 5 फरवरी को मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए वोटिंग हुई थी, इस दौरान सपा ने प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। चुनाव में गड़बड़ी की आशंका जताई, सपा की ओर से दिनभर में कई शिकायतें की गई।

लखनऊ कहलाएगा एक्सप्रेसवे सिटी ऑफ इंडिया, एक-दो नहीं,होंगे नौ एक्सप्रेस वे

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में रोड कनेक्टिविटी को बेहतर हो रही है। प्रदेश को कई हाईवे–एक्सप्रेस वे की सौगात मिल चुकी है।राज्य के बड़े शहरों के साथ छोटे जिलों में भी विकास हुआ है। उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा एक्सप्रेस वे वाला राज्य बना है। सड़कों को भी चौड़ा किया जा रहा है। यूपी देश का इकलौता शहर है लखनऊ से 9 एक्सप्रेसवे गुजरेंगे और ये एक्सप्रेस वे सिटी ऑफ इंडिया कहलाएगा। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में 340.8 किमी लंबा, 6–लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे है। एक्सप्रेस वे लखनऊ जिले में गोसाईगंज के पास चांद सराय गांव को गाजीपुर जिले में एनएच–31 पर हैदरिया गांव के साथ जोड़ता है। यह एक्सप्रेस वे लखनऊ के अलावा बाराबंकी, अमेठी, सुल्तानपुर, अयोध्या, अंबेडकरनगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरता है। वहीं आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे 302 किमी लंबा 6–लेन एक्सेस एक्सप्रेसवे है। ये लखनऊ के मोहान रोड से शुरू होता है और आगरा तक जाता है। एक्सप्रेस वे से आगरा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा,औरैया, कन्नौज, कानपुर, हरदोई, उन्नाव व लखनऊ कनेक्ट होते हैं। इस एक्सप्रेस वे को नेशनल एक्सप्रेस वे–6 के नाम से जाना जाता है। ये एक्सप्रेस वे 6 लेन का है। ये इस साल के अंत तक 8 लेन हो सकता है। इसे अवध एक्सप्रेस वे के नाम से भी जाना जाता है। यह एक्सप्रेसवे लखनऊ के शहीद पथ से शुरू होकर कानपुर के आजाद मार्ग पर खत्म होता है। यह एक्सप्रेसवे 63

किलोमीटर लंबा है। इस एक्सप्रेस वे पर 18 किलोमीटर एलिवेटेड रूट और 45 किलोमीटर ग्रीन फील्ड रूट है। राष्ट्रीय राजमार्ग 230 यानि एनएच 230 जिसे किसान पथ या लखनऊ आउटर रिंग रोड के रूप में भी जाना जाता है।यह उत्तर प्रदेश में मोहनलालगंज से बड़ेल तक जाता है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे–पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को लिंक एक्सप्रेसवे से लिंक किया जाएगा।यह लिंक एक्सप्रेस वे 60 किलोमीटर लंबा है। इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से दिल्ली से पूर्वांचल जाने में समय कम लगेगा।इस लिंक एक्सप्रेसवे के बनने से इन जिलों के लोगों को लखनऊ तक की सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी।गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से प्रयागराज के बीच बन रहा है।इस एक्सप्रेस वे का निर्माण उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण यूपीडा कर रहा है।यह 594 किलोमीटर लंबा है।यह छह लेन का एक्सप्रेस वे है।गोरखपुर–शामली एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश का एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे है।यह गोरखपुर से शुरू होकर शामली तक जाएगा। यह यूपी के 22 जिलों से होकर गुजरेगा।

काली पट्टी बांधकर कोर्ट पहुंचे वकील,प्रयागराज मारपीट मामले को लेकर प्रदर्शन

संवाददाता

लखनऊ। प्रयागराज में वकील के साथ हुई मारपीट मामले को लेकर लखनऊ के वकील प्रदर्शन कर रहे हैं। वकीलों ने आज काम बंद दिया है। सभी काली पट्टी बांध कर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। इधर लखनऊ बार एसोसिएशन ने अधिवक्ताओं के खिलाफ हो रही घटनाओं को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। प्रयागराज में वकील ध्रीरेंद्र सिंह के साथ 4 फरवरी को मारपीट हुई। आरोप है कि उप निरीक्षक अतुल सिंह ने सार्वजनिक रूप से वकील के साथ दुर्व्यवहार किया। उनके कोट पैंट फाड़ दिए गए। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसी वजह से वकीलों में आक्रोश है। बार की तरफ से प्रशासन को अल्टीमेटम दिया गया है। कहा गया है कि अभी सिर्फ काली पट्टी बांधकर प्रदर्शन किया जा रहा है। लखनऊ बार एसोसिएशन में 5000 वकील शामिल हैं। अगर जल्द से जल्द मांगों को नहीं मानता तो वकील सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। कुछ दिन पहले लखनऊ में भी वकील देवकीनंदन पांडेय पर हमला हुआ था। इस मामले को लेकर भी यूपी बार काउंसिल के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान सदस्य परेश मिश्रा ने अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद और पुलिस कमिश्नर अमरेंद्र कुमार सेंगर को पत्र लिखा है। पत्र में बताया गया है कि विभूति खंड थाने में एफआईआर दर्ज होने के बावजूद वकील को लगातार धमकियां मिल रही हैं। 5 फरवरी को अध्यक्ष रमेश प्रसाद तिवारी और महामंत्री ब्रजभान सिंह भानू की अगुआई में कार्यकारिणी की बैठक हुई। बार एसोसिएशन ने प्रस्ताव पारित कर पुलिस आयुक्त प्रयागराज से दोषी पुलिस अधिकारी पर कार्रवाई की मांग की है।

मिल्कीपुर में उपचुनाव नहीं हुआ निष्पक्ष, प्रशासन पर दबाव : अखिलेश यादव

संवाददाता

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर अब आरोप–प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रशासन पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि मिल्कीपुर में उपचुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को मीडिया से बात करते हुए कहा, अगर चुनाव आयोग सख्त कार्रवाई करता तो मिल्कीपुर में निष्पक्ष चुनाव हुआ होता। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं हुआ है, इसलिए मैंने कहा है कि वह (भाजपा) बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ वोटिंग का अधिकार छीनना चाहते हैं। सभी ने देखा है कि भाजपा के लोगों ने वोट के अधिकार को भी छीन लिया है। उन्होंने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा, ध्अयोध्या के एसएसपी राजकरन नय्यर, मिल्कीपुर के एसडीएम राजीव रतन सिंह, सीओ मिल्कीपुर श्रेयस त्रिपाठी, इनायतनगर थाना के एसओ देवेंद्र पांडेय, थाना कुमारगंज के अमरजीत सिंह, थाना खंडासा के संदीप सिंह, जिला विद्यालय निरीक्षक पवन तिवारी पर काफी दबाव है। इतनी सी बात है कि दबाव बहुत है और कोई भी सच नहीं बोल सकता है।

बता दें कि मिल्कीपुर विधानसभा की जनता ने उपचुनाव में अपना 2022 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। यहां के मतदाताओं ने साल 2022 में हुए अब तक के सर्वाधिक 60.23 फीसदी मतदान को पीछे छोड़ते हुए उपचुनाव में 65.35 फीसदी मतदान किया है। इससे पहले समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल ने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मिलकर मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में धांधली को लेकर ज्ञापन सौंपा था। उन्होंने आरोप लगाया कि मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के पोलिंग एजेंटों को मतदान कक्ष से बाहर निकाला गया, पुलिस अधिकारियों द्वारा मतदाताओं की आईडी चेक की गई और दर्जनों पोलिंग स्टेशनों पर भाजपा द्वारा फर्जी वोटिंग कराया गया। आरोप ये भी है कि भाजपा नेताओं द्वारा चार पहिया वाहनों के काफिले के साथ निर्वाचन क्षेत्र में घूम–घूम कर चुनाव को प्रभावित किया गया है।

आरोप लगाने से सपा की डूबती नैया नहीं पार होगी, अखिलेश के बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार

संवाददाता

लखनऊ। अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान सकुशल सम्पन्न हो गया। 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इसके पहले ही आरोप–प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव के बयान के बयान को लेकर पलटवार किया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि मिल्कीपुर उपचुनाव में हार सामने देख अखिलेश यादव बौखला गए हैं! चुनाव आयोग पर आरोप लगाने से सपा की डूबती नैया नहीं पार होगी। जब तक सपा गुंडों, अपराधियों,माफियाओं और दंगाइयों को सपा से बाहर नहीं निकालेगी तब तक साइकिल पंचर ही होती रहेगी और 2027 में सपा प्रत्याशियों की जमानत बचाना भी मुश्किल होगा! दरअसल, समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग को लेकर विवादित टिप्पणी की है। अखिलेश यादव ने कहा है कि यह भाजपा का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है, सफेद कपड़ा हमें भेंट करना पड़ेगा। इस बयान को लेकर बीजेपी सपा पर हमलावार है। अखिलेश यादव के बाद मिल्कीपुर मतदान को लेकर नगीना सांसद

चंद्रशेखर आजाद ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि मिल्कीपुर में भाजपा ने लोकतंत्र का गला घोंटा है। जिस तरह से सरकारी मशीनरी सत्ता के आगे झुक गई है, वोटरों को प्रभावित करने, मतदान में देरी करने, लोगों को धमकाने, वोट न डालने देने का पाप, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, वह अपराध है। सत्ता में रहकर उन्हें लगता है कि वे कभी नहीं जाएंगे लेकिन जिस तरह से वे लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, आने वाले समय में जनता उन्हें जवाब देगी। इतना सब होने के बाद भी मिल्कीपुर में हो सकता है कि नतीजे भाजपा को सबक सिखा दें।

मिल्कीपुर: सीएम योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की प्रतिष्ठादांव पर

संवाददाता

लखनऊ। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल 5 फरवरी को मतदान हुआ। यहाँ भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है।मतगणना 08 फरवरी को होगी। अब रिजल्ट के लिए 08 फरवरी का तो इंतजार करना ही पड़ेगा।एग्जिट पोल तो सिर्फ कयास मात्र हैं, अपने अपने नजरिये से लोग गुणा भाग लगाते हैं लेकिन असल जजमेंट तो मतदाता सुना चुके हैं लेकिन वो ईवीएम में बंद है, जब खुलेगी ईवीएम तभी जीत हार तय होगी और मिल्कीपुर का तय होगा एमएलए।कई बार एग्जिट पोल गलत भी साबित हो चुके हैं। इसलिए 08 तारीख का इंतजार है। चुनाव आयोग के अनंतिम आंकड़ों के मुताबिक शाम 5 बजे तक 65 फीसदी मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।इस सीट पर सपा ने फैजाबाद लोकसभा सीट से सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा जबकि भाजपा ने चंद्रभानु पासवान को मौका दिया। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के संतोष कुमार चौधरी मैदान में उतरे। जनता से बातचीत के आधार पर लगाए जा रहे अनुमानों में सपा–बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर जरूर है। यहां दलित वोटर्स की अच्छी खासी संख्या है। मुस्लिम और यादव गठजोड़ और दलित वोटरों के बूते समाजवादी पार्टी समर्थक अजीत को मजबूत होने का दावा कर रहे हैं।वहीं कुछ लोग वोटिंग प्रतिशत का हवाला देते हुए बीजेपी की जीत की बात भी कह रहे हैं। वे डबल इंजन की सरकार के काम को भी बीजेपी का पलड़ा भारी होने की बात कह रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बीजेपी ने ब्राह्मणों को एकजुट करने में कामयाबी हासिल की है जिसका फायदा मिल रहा है।लेकिन दूसरी तरफ चर्चा यह भी है कि बीजेपी ने बाबा गोरखनाथ का टिकट काट दिया जिसकी वजह से उनके कुछ समर्थकों में नाराजगी दिखाई दी है जिसका बीजेपी को खामियाजा भी भुगतना पड़ा है।

फर्जी बैनामों में लगी मुहर और हस्ताक्षर असली या नकली, फॉरेंसिक लैब में होगी जांच

संवाददाता

आगरा। आगरा में बेशकीमती जमीनों के फर्जी बैनामे यूं ही नहीं कर दिए गए। दलालों ने तहसीलकर्मियों की मिलीभगत से दस्तावेजों में हेरफेर की। बैनामों पर मुहरों से लेकर फर्जी हस्ताक्षर तक कर दिए गए। एसआईटी की जांच में यह बात सामने आई है। टीम अब फर्जी बैनामों को फॉरेंसिक लैब भेज रही है। इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों से भी हस्ताक्षरों का मिलान कराया जा रहा है, जिससे यह पता किया जा सके कि हस्ताक्षर मिलीभगत से किए गए, या फिर धोखे से करा लिए गए। जमीनों के फर्जी बैनामे करने वाले गिरोह पर पुलिस ने पिछले दिनों शिकंजा कसा था। चार मुकदमे दर्ज किए गए। 3 सदर तो 1 शाहगंज थाना में लिखा गया। पुलिस ने तहसील के पूर्व रिकॉर्ड कीपर सहित अन्य को जेल भेजा था। चारों मुकदमों की जांच एसआईटी कर रही है। टीम मास्टरमाइंड की तलाश में लगी है। उधर, एसआईटी की जांच में पता चला है कि गिरोह के सदस्य कर्मचारियों की मिलीभगत से पूरे फर्जीवाड़े को

अंजाम देने में लगे हुए थे। जिन जमीनों के मालिक सामने नहीं आते थे, उन जमीनों के फर्जी बैनामे तैयार कर लिए जाते थे। फर्जी मालिक–खरीदार बन जाते थे। बैनामा बनाने के बाद असली मालिक से सौदेबाजी करते थे। एसीपी सदर विनायक भोसले ने बताया कि एसआईटी फर्जी बैनामों पर लगाई गई मुहरों और हस्ताक्षरों की भी जांच कर रही है। फर्जी बैनामों और स्टांप पर लगीं मुहरें असली हैं तो इससे कर्मचारियों की मिलीभगत की पुष्टि हो जाएगी। इसमें अधिकारियों से अधिक कर्मचारियों की मिलीभगत सामने आ रही है। बैनामों को जांचने और उन पर हस्ताक्षर कराने का काम कर्मचारियों का होता है। उन्होंने ही अधिकारियों को धोखे में रखकर हस्ताक्षर कराए होंगे। वहीं अगर, हस्ताक्षर का मिलान नहीं हुआ तो माना जाएगा कि फर्जी तरीके से हस्ताक्षर और मुहरों का इस्तेमाल किया गया। इसकी जांच विधि विज्ञान प्रयोगशाला में होगी। उधर, बुधवार को भी एसआईटी तहसील में जांच करने पहुंची। हालांकि रिकॉर्ड रूम में नहीं गई। टीम के पहुंचने पर कर्मचारियों की धड़कन बढ़ गईं। टीम ने रिकॉर्ड रूम में काम करने वाले युवकों के बारे में जानकारी ली। कर्मचारियों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस के पहुंचने की वजह से कई बाहरी युवक गायब है।

बाइक सवारों ने गले में झपट्टा मारकर चेन लूटी, रिपोर्ट दर्ज

संवाददाता

अलीगढ़। अलीगढ़–गाजियाबाद हाईवे स्थित दौरुऊ मोड़ के पास टेंपो में सवार युवक से बाइक सवारों ने झपट्टा मारकर चेन लूट ली। पीड़ित ने अज्ञात बाइक सवारों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर देते हुए भारत राघव निवासी सुरजावली, थाना अरनियां बुलंदशहर ने बताया है कि 4 फरवरी की सुबह वह टेंपो में बैठकर अपने गांव जा रहा था। वह साइड की सीट पर बैठा था। जैसे ही टेंपो दौरुऊ मोड़ के पास पहुंचा तो पीछे से आए बाइक सवार दो युवकों ने उसके गले में झपट्टा मारकर चेन लूट ली और मौके से भाग गए। इस बीच पीड़ित का मोबाइल भी सड़क पर गिर गया। हालांकि, मोबाइल बाद में सड़क पर पड़ा मिल गया। पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर ली है, जांच शुरू कर दी है।

ताजमहल में पच्चीकारी देख मुग्ध हुए मंगोलिया के सीमा सुरक्षा प्रमुख, इतिहास के बारे में ली जानकारी

संवाददाता

आगरा। मंगोलिया के सीमा सुरक्षा महानिदेशालय के प्रमुख शारखु लखचिंजावने ने बुधवार को ताजमहल और आगरा किला का भ्रमण किया। ताजमहल में पच्चीकारी देख वह मुग्ध हो गए। पर्यटन मंत्रालय के रशियन गाइड मोहम्मद राशिद ने बताया मंगलवार की शाम को सीमा सुरक्षा प्रमुख आगरा आ गए थे। बुधवार की सुबह करीब सवा नौ बजे ताजमहल पहुंचे। यहां करीब सवा घंटे समय बिताया। पत्थरों पर बनी पच्चीकारी देख दंग रह गए। उन्होंने पच्चीकारी और इसके इतिहास के बारे में पूछा।

रिश्वतखोर महिला पीसीएस अधिकारी का ड्राइवर भी गिरफ्तार, एंटी करप्शन कोर्ट में हुई पेश

संवाददाता

आगरा। मथुरा की जिला पंचायतराज अधिकारी (डीपीआरओ) किरन चौधरी और उनके चालक को 70 हजार रुपये घूस लेते हुए गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को एंटी करप्शन कोर्ट मेरठ में पेश किया गया। वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। विजिलेंस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए तीन टीम का गठन किया था। इसमें रंगेहाथ पकड़ने से लेकर मेडिकल कराने और कोर्ट में पेश करने वाली टीम शामिल रहीं। फरह ब्लाक के झुडावई ग्राम पंचायत में विकास कार्यों के भुगतान को लेकर डीपीआरओ किरन चौधरी पर 70 हजार रुपये घूस मांगने का आरोप है। मामले में पीड़ित प्रताप सिंह राना ने 10 दिन पहले लखनऊ विजिलेंस में शिकायत की थी। इस पर गोपनीय जांच हुई। इसमें आरोप की पुष्टि हुई।

पति के सामने बीवी की लूटी आबरू: चार लोग घर में घुसे, हाथ–पैर बांध किया दुष्कर्म

संवाददाता

आगरा। आगरा के थाना ट्रांस यमुना इलाके में महिला के साथ घर में घुसकर चार लोगों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना के वक्त उसका पति घर में मौजूद था। दो लोगों ने पति को पकड़ लिया। फिर बाकी ने बारी–बारी से उसकी अस्मत के साथ खिलवाड़ किया। वो चीखती रही लेकिन दरिंदों को रहम तक नहीं आया। मामला ट्रांस यमुना क्षेत्र का है। यहां की रहने वाली महिला ने पुलिस को बताया कि एक फरवरी की रात सलीम शाह, अरमान, आमीन और शानू घर में आ गए। सलीम शाह ने उसे पकड़ लिया। अन्य ने पति को दबोच लिया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की। उसके बाद गलत काम किया। इस दौरान पति दरिंदों के सामने गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन आरोपी उसकी अस्मत से खेलते रहे। पीड़िता ने बताया कि इतना ही नहीं आरोपियों ने एक गंदा वीडियो भी बना लिया। जिसे वायरल करने की धमकी देकर शांत रहने के लिए कहा।

संगम में लगाई एक साथ डुबकी...फिर छूट गया हाथ, तलाश में भटक रहा पति

संवाददाता

आगरा। आगरा के बाह क्षेत्र के रहने वाले दंपती प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के लिए गए थे। वहां दोनों ने एक साथ डुबकी लगाई। इसके बाद भीड़ में पत्नी का हाथ छूट गया। भीड़ में पत्नी इस कदर गुम हो गईं कि दूर–दूर तक नजर नहीं आईं। अब पति अपने अन्य साथियों के साथ पत्नी की तलाश में जुटे हैं, लेकिन अभी तक जानकारी नहीं मिल सकी है। बुधवार की सुबह चित्राहाट के सूरजनगर के दंपती कुर्ती सिंह भदौरिया और चंदावती ने संगम में एक दूसरे का हाथ थाम कर डुबकी लगाई थी। डुबकी लगाने के बाद बाहर निकले तो भीड़ में एक दूसरे का हाथ छूट गया। इससे चंदावती बिछुड़ गईं। अपने गांव के साथियों की मदद से चंदावती की तलाश में जुटे हैं।

12 घंटे की शादी: मंदिर में सुबह हुआ रिश्ता

दोपहर में दूल्हा–दुल्हन ने लिए 7 फेरे, सुहागरात से पहले बड़ा कांड

संवाददाता

आगरा। आगरा के एत्माद्दौला क्षेत्र में एक युवक का बुधवार को मंदिर में रिश्ता तय हुआ। दोपहर में दूल्हा–दुल्हन ने सात फेरे लिए। शाम को परिवार वालों को विदा करने के बहाने दुल्हन फरार हो गई। दूल्हे के घरवालों ने पीछा करके शादी कराने वाले युवक और दुल्हन के जीजा को पकड़ लिया। उन्हें पुलिस के हवाले किया गया है। पुलिस मामले की जांच में लगी है। सीता नगर निवासी सनी का डेकोरेशन का काम है। उन्होंने बताया कि 15 दिन पहले मोहल्ले के युवक ने उसकी शादी के लिए फिरोजाबाद के एक युवक से बात की। उसने बताया कि कानपुर की युवती से रिश्ता करा देगा। उसने बताया कि परिवार गरीब है। उसके लिए 35 हजार रुपये खर्च करने होंगे। इस पर वह तैयार हो गए। युवती को देखने के लिए बुधवार का दिन तय किया गया। सनी के परिवार वाले रामबाग स्थित एक मंदिर में आ गए। युवती के साथ बिचौलिये सहित उसकी बहन और जीजा आए थे। पसंद आने पर उन्होंने युवती को सोने की अंगूठी पहना दी। इसके बाद पंडित को बुलाकर सात फेरे भी ले लिए। शाम

को परिवार के लोग घर आ गए। तभी दुल्हन की बहन ने घर जाने के लिए एक ऑटो बुलाया। दुल्हन भी बहन को विदा करने के लिए ऑटो में बैठ गई। इस पर सनी को शक हो गया। वह परिवार के लोगों के साथ ऑटो के पीछे लग गया और रास्ते में रोक लिया। इस दौरान बिचौलिये और दुल्हन के जीजा को पकड़ लिया। दुल्हन और उसकी बहन भाग गए। सनी ने आरोप लगाया कि बिचौलिया शादी कराने के लिए 35 हजार रुपये ले चुका था। वहीं दुल्हन को भी सोने की दो अंगूठी और मंगलसूत्र पहनाए थे। पीड़ित ने दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना प्रभारी का कहना है कि मामले में तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

धार्मिक स्थल में मिली थी जिस महिला की लाश

हत्या का राज तो खुला नहीं...17 वर्षीय भतीजी भी हो गई लापता

संवाददाता

आगरा। आगरा में ताज पूर्वी गेट के पास लकड़हारा मस्जिद में सात महीने पहले हुई महिला की हत्या में पुलिस बेसुराग है। हत्या किसने और क्यों

की? यह आज तक नहीं पता चल सका है। इधर, मृतका के परिवार की किशोरी चार सप्ताह से लापता है। परिजन बेटी की तलाश में भटक रहे हैं। उन्हें पुलिस से शिकायत पर भी राहत नहीं मिल पा रही है। 19 मई 2024 को ताजमहल पूर्वी गेट के पास स्थित लकड़हारा मस्जिद में 42 वर्षीय महिला की हत्या कर दी गई थी। महिला का शव अर्धनग्न हालत में मिला था। मृतका के भाई ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस हत्याकांड की गुत्थी नहीं सुलझा सकी है। शक के दायरे में आए आरोपी का फोरेंसिक विज्ञानी की मदद से प्रोफाइल भी तैयार कराया गया। ताजगंज का युवक शक के दायरे में है। उधर, मुकदमे के वादी और मृतका के भाई की 17 वर्षीय बेटी गायब हो गई है। वह 10 जनवरी की दोपहर तीन बजे दवा लेने के लिए निकली थी। तब से घर नहीं लौटी है। उसकी तलाश की, लेकिन पता नहीं चल सका। इस पर थाना ताजगंज में रिपोर्ट दर्ज कराई। बाद में पता चला कि बस्ती की एक युवती उसे ले गई है। युवती हिमाचल प्रदेश की रहने वाली है। ताजगंज में उसका मायका है। पति दुकान चलाता है। पिता ने बेटी के साथ अनहोनी की आशंका जाहिर की है। पुलिस का कहना है कि किशोरी की तलाश की जा रही है। काल डिटेल खंगाली गई है। जिस युवती पर आरोप है कि उससे और परिवार के लोगों से बात की गई है। उनका कहना है कि युवती उनकी दुकान पर आती थी। वह कहां गई, किसी को पता नहीं है। एसीपी ताज सुरक्षा सैय्यद अरीब अहमद का कहना है कि पुलिस टीम को लगाया गया है।

इम्तिहान में विवि फेल: एलएलबी तृतीय सेमेस्टर में कम निकले पेपर, परीक्षा स्थगित, जल्द तय की जाएगी दूसरी तिथि

संवाददाता

अलीगढ़। राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय (आरएमपीएसयू) की लापरवाही ने एलएलबी के 1200 विद्यार्थियों की तैयारियों पर पानी फेर दिया। 5 फरवरी को करीब पौने ग्यारह बजे जब छात्रों को प्रश्नपत्र वितरित किया जा रहा था तब अचानक पता चला कि पेपर कम पड़ गए हैं। सभी केंद्रों से जब सूचना पहुंची तो परीक्षा नियंत्रक ने तत्काल एलएलबी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा को स्थगित कर दिया। परीक्षा स्थगित होने के बाद परीक्षार्थियों ने हंगामा किया। छात्रों का कहना था कि वह पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे लेकिन अब परीक्षा कराई ही नहीं जा रही है। 5 फरवरी को एलएलबी तृतीय सेमेस्टर की रेगुलर और पूर्व परीक्षार्थियों की दूसरी पाली की परीक्षा सुबह 10:30 बजे से 12:30 बजे थी। इनमें रेगुलर के करीब 1200 और पूर्व परीक्षार्थियों की संख्या करीब 300 है। यह परीक्षा हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ में बने परीक्षा केंद्रों पर कराई जा रही थी। परीक्षा देने के लिए परीक्षार्थी अपने–अपने कक्ष में पहुंच गए। कक्ष में मौजूद परीक्षार्थियों को प्रश्नपत्र वितरित किए जाने लगे, तभी नोडल केंद्रों पर रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या के सापेक्ष सीलबंद पैकेट में "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" विषय के प्रश्न पत्र कम निकले। शहर के डीएस कॉलेज में 324 और एसवी कॉलेज में 170 परीक्षार्थी थे, लेकिन उनके लिए "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" विषय के पेपर बहुत कम पहुंचे। अन्य केंद्रों पर भी यही स्थिति रही। जब विद्यार्थियों को पेपर नहीं मिला तो उन्होंने क्लासरूम में ही

हंगामा शुरू कर दिया। इस पर नोडल परीक्षा केंद्र प्रभारियों ने विवि के अधिकारियों से बात की, जिस पर उन्होंने रेगुलर परीक्षार्थियों की परीक्षा स्थगित करने का आदेश दे दिया। हालांकि, पूर्व परीक्षार्थियों की "इंडियन एविडेंस एक्ट" शीर्षक पेपर की परीक्षा करा दी गई। विश्वविद्यालय में हाथरस, कासगंज, एटा और अलीगढ़ में रेगुलर परीक्षार्थियों की संख्या करीब 1200 है। रेगुलर विद्यार्थियों के लिए प्रश्न पत्र कम छपकर आए थे, जबकि पूर्व परीक्षार्थियों की परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र ज्यादा छप गए थे। मॉडरेशन के दौरान त्रुटिवश से टाइटल पेपर अदल–बदल गए थे। इसलिए पेपर "इंडियन एविडेंस एक्ट" ज्यादा और "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" कम छप गए। हालांकि, दो–चार दिन में स्थगित परीक्षा होने की तिथि घोषित कर दी जाएगी। अनुत्तीर्ण और पुनर्परीक्षा देने वाले परीक्षार्थियों को "इंडियन एविडेंस एक्ट" पेपर की परीक्षा देनी थी। रेगुलर परीक्षार्थियों को "भारतीय साक्ष्य अधिनियम" पेपर की परीक्षा देनी थी।

महिला ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी, मायके वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप

संवाददाता

अलीगढ़। क्षेत्र के गांव चाऊपुर में रेलवे ट्रैक पर एक विवाहिता ने गृहक्लेश के चलते रेल के आगे कूदकर खुदकुशी कर ली। महिला के मायके वालों ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज

दिया है। आरती (22) पत्नी धर्मेंद्र निवासी चाऊपुर की शादी दिसंबर 2023 में हुई थी। धर्मेंद्र मजदूरी करता है। उस पर चार माह का बेटा भी है। इसी घर में उसकी बहन पूजा की भी शादी हुई है। 4 फरवरी की शाम को घर में आरती का ससुरालियों से विवाद हो गया। इसके बाद नाराज होकर वह घर से चली गई। खोज करने पर आरती का शव रेलवे लाइन पर मिला। जानकारी होने पर महिला के मायके वाले पहुंचे गए। मृतका के भाई टीटू पुत्र धर्मवीर सिंह ने निवासी बैरमनगर, थाना छतारी बुलंदशहर ने थाना जवां में रिपोर्ट दर्ज कराई है। तहरीर में बताया है कि दोनों बहनों की शादी में हुई खर्च से उनके ससुराल वाले संतुष्ट नहीं थे। अतिरिक्त दहेज के लिए उनका मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न किया जा रहा था। आरोप है कि मंगलवार की रात धर्मेंद्र, दीपक, रामगोपाल, मां रामवती, भाई शंभू व ब्रजमोहन, जिठानी गंगा देवी ने उसे पीटा। बड़ी बहन पूजा को कमरे में बंद कर दिया। आरती को मारकर रेलवे लाइन पर डाल दिया। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली है।

जिस प्रखर ने बांके बिहारी कॉरिडोर के लिए 510 करोड़ रुपये दान का दिया शपथपत्र, उसकी संपत्ति होगी जब्त

संवाददाता

आगरा। आगरा के बिल्डर प्रखर गर्ग सहित 197 आरोपियों की संपत्ति बीएनएस की धारा 107 के तहत जब्त की जाएगी। संपत्ति को चिह्नित करने के लिए नगर निगम, आयकर, परिवहन, निबंधन कार्यालय एवं जीएसटी को पत्र लिखे गए हैं। कोर्ट में रिपोर्ट देने के बाद अनुमति ली जाएगी। पुलिस ने हाल ही में नकली दवा, घी आदि के मामले पकड़े थे। जमीनों के फर्जीवाड़ा करने वाले जेल भेजे थे। कई अन्य अपराधियों पर भी कार्रवाई की गई। यह देखा जा रहा है कि अपराध से संपत्ति किसने और कितनी अर्जित की। इसमें बिल्डर प्रखर गर्ग का भी नाम है। उस पर भी केस दर्ज हैं। आईपीसी में पुलिस संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत करती थी। भारतीय न्याय संहिता में धारा 107 में विवेचक को शक्तियां मिली हैं। वह संपत्ति जब्तीकरण के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। उन्हें साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे कि आरोपी ने संपत्ति अपराध से अर्जित की है। कोर्ट की अनुमति पर आरोपी की

संपत्ति को जब्त किया जा सकता है। डीसीपी सिटी सूरज कुमार राय ने बताया कि पुलिस आयुक्त जे रविन्दर गौड ने कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इस पर आरोपियों की सूची तैयार की गई। इसके बाद संपत्ति चिह्नित की जा रही है। कुछ की रिपोर्ट भी कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है। अनुमति मिलने पर संपत्ति का जब्तीकरण कर दिया जाएगा। थाना हरीपर्वत के प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि बिल्डर प्रखर गर्ग की संपत्ति चिन्हित करने की कार्रवाई की जा रही है। इसके लिए आयकर, जीएसटी, परिवहन, निबंधन कार्यालय, नगर निगम के अधिकारियों को पत्र लिखे हैं। मुकदमे में नामजद आरोपी के नाम क्या–क्या संपत्ति है। यह पता किया जा रहा है। फर्म के बारे में भी जानकारी मांगी गई है। संपत्ति चिन्हित करने के बाद विवेचक कोर्ट में प्रार्थनापत्र देंगे।

ये हैं 70 वर्षीय सूरजभान...जिन्हें जीते जी मार दिया, मंत्री की सिफारिश, तब मिला जिंदा होने का प्रमाण पत्र

संवाददाता

आगरा। आगरा में समाज कल्याण विभाग में लापरवाही का आलम देखिए। जिंदा सूरजभान को मृत दर्शा दिया। पोर्टल पर गलत रिपोर्ट फीड होने से पेंशन बंद हो गई। एक साल तक वृद्ध ब्लॉक से तहसील, विकास भवन व कलेक्ट्रेट तक दौड़ता रहा। थककर समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से गुहार लगाई तो 24 घंटे में दोबारा पेंशन शुरू हो गई है। बड़ागांव निवासी 70 वर्षीय सूरजभान पुत्र स्व. पंजाब सिंह को हर माह एक हजार रुपये वृद्धावस्था पेंशन मिलती थी। 2023–24 में सर्वेयर ने लापरवाही बरती। पेंशनर सत्यापन में आंख मूंद कर रिपोर्ट में जिंदा सूरजभान को मृत दर्शा दिया। पोर्टल पर मृतक की रिपोर्ट फीड होने से पेंशन रुक गई। एक साल से बुजुर्ग सरकारी दफ्तरों में चक्कर काटता रहा। लेकिन, उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई। फिर बुजुर्ग ने समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण से गुहार लगाई। मंत्री ने तत्काल मामले का संज्ञान लेते हुए समाज कल्याण निदेशक से नाराजगी व्यक्त की। गलत डाटा फीडिंग व सत्यापन में लापरवाही पर फटकार लगाई। जिसके बाद तत्काल निदेशालय से सही डाटा फीड किया गया। 24 घंटे में ही पेंशन स्वीकृति प्रमाणपत्र बन गया। समाज कल्याण अधिकारी प्राची जोशी पेंशन

स्वीकृति का प्रमाणपत्र लेकर बुधवार को बड़ागांव पहुंचीं। बुजुर्ग सूरजभान को जब पेंशन शुरू होने और प्रमाणपत्र दिखाया तो उनके चेहरे पर चमक आ गई। प्राची जोशी ने बताया कि मार्च में पहली करीब एक साल की पेंशन एकमुश्त लाभार्थी के खाते में आएगी। तकनीकी त्रुटि के कारण उनका नाम पेंशन लाभार्थियों की सूची से हट गया था। जिसे मंत्री के निर्देश पर ठीक कर लिया गया है।

प्रारंभिक जांच में प्रधानाध्यापक की लापरवाही आई सामने

संवाददाता

अलीगढ़। गांव जलालपुर के प्राथमिक विद्यालय में स्कूल का गेट गिरने से हुई कक्षा दो के छात्र अनुज की मौत के मामले में तीन खंड शिक्षा अधिकारियों की टीम ने बुधवार को स्कूल पहुंचकर जांच की। प्रारंभिक जांच में प्रधानाध्यापक की लापरवाही सामने आई है। समिति बृहस्पतिवार को अपनी रिपोर्ट बीएसए को सौंप देगी। मंगलवार को शाम तीन बजे छुट्टी के दौरान स्कूल का गेट गिर गया था और इसके नीचे दबकर कक्षा दो के छात्र अनुज की मौत हो गई थी। इस मामले में बीएसए ने सतीश चंद्र शर्मा खंड शिक्षा अधिकारी शहर, रामशंकर कुरील लोधा और सुबोध कुमार चंडौस की संयुक्त समिति बनाई थी। टीम जिला समन्वयक ज्ञानेंद्र गौतम के साथ बुधवार सुबह नौ बजे विद्यालय में पहुंच गई। ढाई घंटे तक विद्यालय में रहकर जांच की। इस दौरान पढ़ने वाले विद्यार्थियों, शिक्षकों और ग्रामीणों से बात की व उनके बयान दर्ज किए। गांव के प्रकाश चंद, रामस्वरूप, रवेंद्र, इंद्रपाल, सुरेश गौतम, तालेवर सिंह आदि ने बताया कि गेट के सामने नाली पर जाल नहीं है, यहां भी कोई घटना हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस मामले में शिक्षकों की लापरवाही रही है। गेट को सही नहीं कराया गया, उसे रस्सी से बांधकर रोका गया था। अध्यापकों ने टीम को बताया कि गेट लगने के कुछ महीने बाद ही जोड़ की वेल्डिंग टूट गई थी, और उसे फिर से वेल्ड कराया गया था। वेल्डिंग करने वाले मिस्त्री ने इसे फिर से टूटने का भरोसा नहीं दिया था। जांच अधिकारियों ने नाली पर जाल लगवाने और गेट के लिए नया होलपास लगवाने के लिए कहा है। बीएसए डाक्टर राकेश कुमार सिंह ने बताया कि रिपोर्ट के परीक्षण के बाद कार्रवाई की जाएगी। बुधवार को पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही बच्चे का शव गांव पहुंचा परिवार में कोहराम मच गया और गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। सभी परिजनों का रो–रो कर बुरा हाल है। गमगीन माहौल में परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार किया। विद्यार्थियों ने बताया कि अचानक गेट गिरने के बाद जब अनुज गेट के नीचे दब गया, उसे देख विद्यालय की एक शिक्षिका बेहोश हो गई। दूसरी शिक्षिका प्रधानाध्यापक को बुलाकर लाई, इसके बाद गेट को हटाया गया।

हर रंग का अपना है एक खास महत्व

रोज डे पर गुलाब देने से पहले जान लें किस कलर का क्या है मतलब

एजेंसी

गुलाब का फूल प्यार, खूबसूरती और भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। रोज डे के मौके पर गुलाब देना एक खास परंपरा है, जो प्रेम और सम्मान को जाहिर करने का एक अनूठा तरीका है। वेलेंटाइन्स डे से एक हफ्ता पहले वेलेंटाइन वीक शुरू हो जाता है। इसकी शुरुआत रोज डे से होती है। हर रंग के गुलाब का अपना एक खास मतलब होता है, जो भावनाओं को गहराई से जाहिर करता है। आइए जानते हैं कि अलग–अलग रंग के गुलाबों का क्या मतलब होता है और किस अवसर पर कौन–सा रंग चुनना सही होगा। लाल गुलाब प्रेम और जुनून का प्रतीक है। यह रोमांस और गहरी भावनाओं को दर्शाता है। रोज डे पर लाल गुलाब देना यह संकेत देता है कि आप किसी के लिए काफी डीप फीलिंग्स रखते हैं। यह फूल प्रेमियों के बीच सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है और अक्सर वैलेंटाइन डे या अन्य रोमांटिक अवसरों पर दिया जाता है। गुलाबी गुलाब कोमलता, प्रशंसा और आभार का प्रतीक है। हल्के गुलाबी रंग के गुलाब मासूमियत और मिठास को दर्शाते हैं, जबकि गहरे गुलाबी रंग के गुलाब आभार और प्रशंसा को जाहिर करते हैं। यह फूल दोस्तों और परिवार के सदस्यों को देने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। सफेद गुलाब शुद्धता, मासूमियत और नई शुरुआत का प्रतीक है। यह फूल शांति और सम्मान को भी दर्शाता है। सफेद गुलाब अक्सर शादियों और धार्मिक समारोहों में इस्तेमाल किया जाता है। इसे किसी को आशीर्वाद देने या नई शुरुआत की शुभकामनाएं देने के लिए भी दिया जा सकता है। पीला गुलाब खुशी, दोस्ती और उत्साह का प्रतीक है। यह फूल दोस्ती और आपसी समझ को दर्शाता है। पीले गुलाब को किसी दोस्त को देकर आप उनकी खुशी और सफलता की कामना कर सकते हैं। हालांकि, कुछ संस्कृतियों में पीले गुलाब को विदाई या अलगाव का प्रतीक भी माना जाता है। नारंगी गुलाब उत्साह, एनर्जी और उत्साह का प्रतीक है। यह फूल किसी को प्रेरित करने या उनकी उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। नारंगी गुलाब रोमांटिक और प्लेटोनिक दोनों तरह के रिश्तों में इस्तेमाल किया जा सकता है। बैंगनी गुलाब रहस्य, आकर्षण और रॉयल फीलिंग्स का प्रतीक है। यह फूल किसी को खास महसूस कराने के लिए एकदम सही है। बैंगनी गुलाब अक्सर उन लोगों को दिया जाता है, जिनका आप खूब सम्मान करते हैं। काला गुलाब दुख, विदाई और अंत का प्रतीक है। हालांकि, यह फूल रहस्य और नाटकीयता को भी दर्शाता है। काले गुलाब को अक्सर साहित्य और कला में प्रतीकात्मक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। इसे असल जिंदगी में कम ही दिया जाता है, क्योंकि यह नेगेटिव भावनाओं से जुड़ा होता है। नीला गुलाब रहस्य, असंभव और अद्भुत का प्रतीक है। यह फूल उन लोगों को दिया जाता है, जो कुछ अलग और अनोखा चाहते हैं। नीले गुलाब को अक्सर क्रिएटिव और कल्पनाशील लोगों के लिए चुना जाता है।

महाराष्ट्र में गुलियन बेरे सिंड्रोम ने मचाई तबाही

एजेंसी

वर्तमान समय में देश कई प्रकार की गंभीर बीमारियों और संक्रामक बीमारियों की चपेट में है। पहले एचएमपीवी और फिर एच5एन1 के संक्रमण ने हेल्थ एक्सपर्ट्स की चिंता को बढ़ाया है। वहीं अब महाराष्ट्र के कई शहरों में गिलियन बैरे सिंड्रोम के मामले में बढ़ोत्तरी देखने को मिली है। जिससे लोगों के मन में इस बीमारी का डर बैठ गया है। राज्य में लोग पहले से ही बर्ड फ्लू के संक्रमण से परेशान थे। लेकिन इसी बीच जीबीएस की एंट्री ने हेल्थ क्षेत्र में एक्स्ट्रा दबाव बढ़ा दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गुलियन बेरे सिंड्रोम की वजह से पुणे में एक मरीज की मौत हो गई है। राज्य में इस बीमारी से होने वाले पहली संदिग्ध मौत है। बता दें कि पुणे में करीब 100 से ज्यादा लोगों में इस बीमारी के मामले दर्ज किए गए हैं। अलग–अलग अस्पतालों में इलाज करा रहे इन मरीजों में करीब 16 मरीज वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। महाराष्ट्र हेल्थ विभाग द्वारा किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि 9 साल से कम उम्र के 19 मरीज और 65–80 साल वाले करीब 10 मरीज हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को इस बीमारी ने प्रभावित किया है।

क्वीन विक्टोरिया से जुड़ा है रोज डे का कनेक्शन ?

बेहद खूबसूरत है यह कहानी

एजेंसी

फरवरी का महीना प्यार, रोमांस और अपनी भावनाओं को जाहिर करने के लिए जाना जाता है। इस महीने ही प्रेमियों का दिन वेलेंटाइन्स डे आता है। वेलेंटाइन वीक की शुरुआत 7 फरवरी को रोज डे से होती है। इस दिन लोग अपने लवर्स को रोज देकर अपने प्यार, दोस्ती और सम्मान को व्यक्त करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दिन का एक ऐतिहासिक संबंध क्वीन विक्टोरिया और उनकी प्रेम कहानी से भी जुड़ा है? जी हां, रोज को प्यार का प्रतीक बनाने में विक्टोरियन युग की एक अहम भूमिका रही है। आइए जानते हैं कि इस परंपरा की शुरुआत कैसे हुई और वेलेंटाइन वीक की शुरुआत रोज डे से ही क्यों होती है। 19वीं सदी में महारानी विक्टोरिया (1837–1901) का शासन ब्रिटेन में सांस्कृतिक बदलावों के लिए जाना जाता है। इसी दौर में फ्लोरियोग्राफी (फूलों की भाषा) को बहुत महत्व मिला। इस समय लोग अपने प्यार और भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने में झिझक महसूस करते थे। इसलिए उन्होंने फूलों के जरिए से अपनी भावनाओं को जाहिर करना शुरू किया। रोज डे पर प्रेमी जोड़ा एक दूसरे को गुलाब का फूल देता है और प्यार का इजहार करता है। लाल गुलाब को प्यार का प्रतीक माना जाता है और मुगलकाल से गुलाब देने का चलन चला आ रहा है। कहा जाता है मुगल बेगम नूरजहां को लाल रंग के गुलाब बहुत पसंद हुआ करते थे। उन्हें खुश करने के लिए मुगल शासक जहांगीर रोज करीब 1 ताजा गुलाब उन्हें भेंट के रूप में भेजा करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि क्वीन विक्टोरिया को भी गुलाब बहुत पसंद हुआ करते थे। उन्होंने पति प्रिंस अल्बर्ट को प्यार का इजहार करते वक्त लाल रंग के गुलाब के फूल दिए थे। महारानी विक्टोरिया के वक्त से ही लोग 7 फरवरी को रोज डे के रूप में मनाते रहे हैं। इस दिन आप अपने चाहने वाले को गुलाब का फूल देकर उन्हें खुश कर सकते हैं। गुलाब का फूल सबसे सुंदर माना जाता है। इसकी खुशबू आपके रिश्तों को भी ऐसे ही महकाती रहे, इसलिए गुलाब का फूल गिफ्ट किया जाता है। लाल रंग को प्यार का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में प्यार की वीक यानि वैलेंटाइन वीक की शुरुआत गुलाब के साथ करना और भी अच्छा माना जाता है। आप अपने लव पार्टनर के अलावा किसी दोस्त या जिसे स्पेशल फील करवाना चाहते हैं उन्हें गुलाब का फूल गिफ्ट कर सकते हैं।

हर टेडी बियर देता है एक अलग संदेश, सोच समझकर करें गिफ्ट

एजेंसी, टेडी डे हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है। टेडी बियर सिर्फ एक खिलौना नहीं, बल्कि यह भावनाओं का जाहिर करने का खूबसूरत जरिया भी होता है। हर टेडी बियर का रंग अलग–अलग भावनाओं को दर्शाता है। अगर आपको कोई टेडी गिफ्ट करता है, तो उसके रंग के आधार पर आप उनके दिल की बात समझ सकते हैं। अगर आप किसी को पसंद करते हैं या आपका कोई क्रश है तो उसे ऐसा टेडी बियर गिफ्ट करें जो उनके प्रति आपके आकर्षण की अभिव्यक्ति करे। वहीं अगर किसी दोस्त या पार्टनर को अलग रंग और आकार का टेडी तोहफे में दे सकते हैं। टेडी बियर के रंग को समझ कर दिल की बात जानने की कोशिश की जा सकती है। हर टेडी बियर एक अलग संदेश देता है, इसलिए इसे सोच–समझकर गिफ्ट करें। लाल टेडी बियर का मतलब है ए स्वअम ल्वन. बिना शब्दों के प्रेम के इजहार के लिए लाल रंग का टेडी बियर गिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई लाल रंग का टेडी बियर दे रहा है तो इसका मतलब है कि वह आपसे प्यार करता है। लाल टेडी बियर रिश्ते को मजबूत बनाने और प्यार जताने के लिए दिया जाता है। अक्सर कपल्स प्रपोज करने के लिए गिफ्ट करते हैं। पीले गुलाब की तरह पीला टेडी भी दोस्ती और नई शुरुआत का प्रतीक है। पीला रंग खुशी, दोस्ती और सकारात्मकता का प्रतीक है। अगर कोई आपको येलो टेडी देता है, तो इसका मतलब है कि वह आपको एक अच्छा दोस्त मानता है। यह किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने का संकेत भी हो सकता है। भूरे रंग के टेडी भी बाजार में उपलब्ध रहते हैं। ये केयर और मजबूती का प्रतीक है। अगर आप किसी को ब्राउन टेडी देते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका रिश्ता मजबूत और भरोसेमंद है। जब आप किसी को सपोर्ट और मजबूती का एहसास कराना चाहते हैं तो इस तरह का टेडी तोहफे में दें। नीला रंग सच्चे प्यार और भरोसे का प्रतीक है। अगर कोई आपको ब्लू टेडी गिफ्ट करता है, तो इसका मतलब है कि वह आपको अपनी लाइफ का अहम हिस्सा मानता है। यह दर्शाता है कि आपका रिश्ता वफादारी और ईमानदारी पर टिका है। जब आप किसी को दिखाना चाहते हैं कि आप हमेशा उनके साथ रहेंगे, तो नीले रंग का टेडी बियर दें। पिंक टेडी का मतलब है कि कोई आपको पसंद करता है और आपकी केयर करता है। यह पसंद और रोमांटिक फीलिंग्स का संकेत देता है।

रीमेक के जाल में इस बार फंसी सान्या मल्होत्रा

जेन जी के जमाने में बीती सदी की फिल्म

एजेंसी

एक और हफ्ता, एक और रीमेक, और, एक और फिल्म का अपने समय के दर्शकों से सीधा तारतम्य न बिठा पाने की कमजोरी। हिंदी सिनेमा अपनी अलग काल्पनिक दुनिया में खोता दिख रहा है। वह कहानियां साउथ से पहले भी उठाता रहा है। लेकिन, तब के सिनेकार वहां के मनोविज्ञान को समझकर उसे हिंदी सिनेमा के दर्शक के हालात के मुताबिक नए रूप में ढाल लेते थे। अबके सिनेमा के सूरमाओं की समस्या दूसरी ही है। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल भारत में हो तो वहां शो खत्म होते ही बता देंगे कि इसका रिव्यू इसके सिनेमाघरों या ओटीटी, जहां पर भी पहले हो, वहां रिलीज होने से पहले लिखना मना है। लेकिन, यही चौधराहट इनकी विदेशी फिल्म फेस्टिवल में नहीं चलती। फिल्म फेस्टिवल में दिखाई जाने वाली फिल्मों की समीक्षाएं लिखने की पाबंदी गोवा फिल्म फेस्टिवल के अलावा भी दुनिया के किसी दूसरे फिल्म फेस्टिवल में होती होगी, लगता तो नहीं है। फिल्म 'मिसेज' जैसा कि नाम से जाहिर है, एक ब्याहता की कहानी है। फिल्म को गोवा फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया तो शो हाउसफुल था। फेस्टिवल में मुख्य धारा की कोई फिल्म चलकर आ जाए तो इतना उत्साहित होना तो बनता है। संकेत इसका ये है कि लोग सिनेमाघरों में फिल्में देखने के लिए दांत चियारे बैठे रहते हैं। फिल्म तो कोई बनाए जो उनको बुक्का फाड़कर रोने या फिर ठहाका लगाकर हंसने का मौका दे। जियो स्टूडियोज इस फिल्म की निर्माता कंपनी है। अभिनेता से निर्माता बने हरमन बावेजा ने उसी के सहयोग से फिल्म बनाई। जियो का अपना ओटीटी एप भी है, लेकिन ये फिल्म रिलीज हो रही है जी के ओटीटी जी5 पर। कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी ये समझने में फेल है कि नेटवर्क18 के पास जब वूट ओटीटी हुआ करता था, तब उसकी सीरीज नेटफ्लिक्स पर आती थी। अब जियो सिनेमा है तो मामला जी5 तक पहुंच रहा है। जियो सिनेमा भी अपने ग्राहकों से पैसे लेता है, वूट भी लेता था, लेकिन जरा सा भी बेहतर फिल्म या सीरीज जियो स्टूडियोज की दिखे तो वह इस ओटीटी पर नहीं आती। सान्या मल्होत्रा की गाड़ी ऐसे किरदारों में स्टार्टिंग प्वाइंट से ही थर्ड गियर में आ जाती है जहां पूरा का पूरा फोकस उनके किरदार पर ही हो। 'दंगल'बाला इसके पहले 'पगलैट' और 'कटहल' में भी ऐसा कर चुकी हैं। ये तीनों की तीनों फिल्में डार्क ह्यूमर श्रेणी की फिल्में मानी जा सकती हैं। और, इन तीनों फिल्मों में सान्या मल्होत्रा के कंधे पर पूरी फिल्म को खींचने की जिम्मेदारी रही। निर्देशक आरती कडव की चर्चा इसके पहले फिल्म 'कार्गो' को लेकर खूब हुई। इस बार उन्होंने एक मलयालम फिल्म 'द ग्रेट इंडियन किचन' का रीमेक बनाया है। नृत्य में महारत हासिल कर चुकी एक युवती शादी होकर डॉक्टरों के एक ऐसे परिवार में आ जाती है, जिसके मर्दों को कैसरॉल में रखी गर्म रोटी खाना भी अपनी तौहीन लगती है। उन्हें सीधे चूल्हे से उतरी हुई रोटी यानी फुल्के अपनी प्लेट में चाहिए। बाप–बेटा दोनों एक ही रोग से ग्रसित दिखते हैं और वह हैं खामखां की मर्दों वाली चौधराहट। मसलन पिताजी को मिक्सी और सिलबट्टे में पिसी गई चटनियों की इतनी परख है, कि चखते ही बता देते हैं। बिरयानी उन्हें दम लगाकर पकाई हुई चाहिए। कुकर में बने तो वह इसे पुलाव कहते हैं। लफड़े क्यों नहीं मारता इन दोनों को कोई। देखा, सिर्फ तीन लाइनें पढ़ने में आपको झुंझलाहट हो गई, सोचिए उस नवब्याहता को जिसे ये रोज झेलना पड़ रहा है। कहानी की अंतर्धारा सा बहता घर की किचन का एक पाइप है। ये बूंद बूंद टपकना शुरू होता है। उधर बहू का मानसिक त्रास बढ़ता जाता है। इधर पाइप से रिसने वाले पानी की रफ्तार बढ़ती जाती है। पति महिलाओं का डॉक्टर है। उसे इस बात की गिनती करनी आती है कि मासिक धर्म के कितने दिन बाद संभोग करो तो पत्नी शर्तिया गर्भवती होगी! उसे अपनी पत्नी की और कोई परवाह नहीं। घड़ा तो नहीं लेकिन किचन में रिसते पाइप के नीचे रखी बाल्टी जरूर भरने लगती है। और, जैसे पाप का घड़ा फूटे तो सत्यानाश तय है, वैसे ही यहां खिचखिच की बाल्टी भरती है और सवा सत्यानाश कर देती है। कहानी सपाट है। बहुत ज्यादा सिनेमाई प्रयोगों की यहां गुंजाइश नहीं है। मलयालम सिनेमा अधिकतर ऐसा ही होता है। वहां पिक्चर बनाने वाले ग्लैमर पर नहीं कहानी पर खेलते हैं। उन्हें अपना दर्शक वर्ग बहुत सटीक पता है। आरती कडव को पता ही नहीं कि ये फिल्म उन्होंने किसके लिए बनाई, सिनेमा हॉल जाने वाले दर्शकों के लिए या फिर मोबाइल, लैपटॉप या कहीं भी फिल्म देख लेने वालों के लिए! अपनी निर्देशक जैसी ही कन्फ्यूज ये फिल्म भी है और फिल्म के कलाकार भी।

सिद्धार्थ-नीलम के संगीत समारोह में ससुराल वालों संग दिखीं प्रियंका

मन्नारा भी साथ आईं नजर

एजेंसी, प्रियंका चोपड़ा के भाई सिद्धार्थ चोपड़ा अपनी मंगेतर नीलम उपाध्याय के साथ शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। शादी से पहले का जश्न जोरों पर है, बुधवार दोपहर को हल्दी की रस्म होगी। अब प्रियंका चोपड़ा परिवार संगीत की रात के साथ डांस, संगीत और कुछ मौज–मस्ती के लिए तैयार है। प्रियंका की मां मधु चोपड़ा, चचेरी बहन मन्नारा चोपड़ा और मिताली हांडा पहले ही जश्न में शामिल हो चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा भाई सिद्धार्थ चोपड़ा की प्री–वेडिंग सेलिब्रेशन के लिए मुंबई में एक शानदार स्ट्रैपलेस गाउन में पहुंचीं। बुधवार शाम को जब प्रियंका अपनी कार से उतरीं और वेन्यू के एंट्री गेट के पास पैपराजी के लिए पोज दिया तो उन्होंने लाइमलाइट बटोरी। इससे पहले प्रियंका अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ हल्दी समारोह में शामिल हुई थीं। प्रियंका चोपड़ा आज रात भाई सिद्धार्थ की शादी से पहले के समारोह में शामिल होने के लिए किसी प्रिंसेस की तरह दिख रही थीं। उन्होंने मोटिफ्स और मोतियों से सजी आइवरी गाउन पहनी थी और बिल्कुल किसी परी जैसी लग रही थीं। प्री–वेडिंग फंक्शन में अभिनेत्री को अपने पति निक जोनस के माता–पिता के साथ पोज देते हुए देखा गया। प्रियंका चोपड़ा की मां मधु चोपड़ा और चचेरी बहन मन्नारा चोपड़ा भी सिद्धार्थ के प्री–वेडिंग फंक्शन में नजर आईं। वे दोनों भी तस्वीरों के लिए पोज देती नजर आईं। इससे पहले दिन में, प्रियंका चोपड़ा के साथ दूल्हा–दुल्हन का माही

वे गाने पर थिरकते हुए एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया था। पारंपरिक पीले रंग के परिधान पहने इस जोड़े को अपनी शादी के जश्न का आनंद लेते देखा गया, जबकि प्रियंका भी मुस्कुराती हुई नजर आईं। वे छैया छैया और गल्लां गूड़ियां पर भी डांस करते नजर आए। अगस्त 2024 में सगाई करने वाले सिद्धार्थ और नीलम अब शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं।

लंबे समय बाद साथ नजर आए तीनों खान, दिखा भाईचारा, इन सितारों ने लगाए चार चांद

एजेंसी

बुधवार की रात अभिनेता आमिर खान के बेटे जुनैद खान और श्रीदेवी की बेटी खुशी कपूर की फिल्म 'लवयापा' की स्क्रीनिंग हुई। स्पेशल स्क्रीनिंग में बॉलीवुड के दिग्गज सितारों ने शिरकत की। इस दौरान बॉलीवुड के तीनों खान भी नजर आए। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर आमिर खान ने शाहरुख और सलमान का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। तीनों खानों को आखिरी बार अनंत अंबानी की वेडिंग में देखा गया था। 'लवयापा' की स्पेशल स्क्रीनिंग को और भी स्पेशल बनाने के लिए शाहरुख खान और सलमान खान भी शामिल हुए। अभिनेताओं के आने पर आमिर ने बड़ी ही गर्मजोशी के साथ उनका स्वागत किया। आमिर ने शाहरुख को गले लगाया और तस्वीरों के लिए पोज दिया। इस स्पेशल स्क्रीनिंग में आमिर खान को अपने परिवार के साथ देखा गया। जुनैद को सपोर्ट करने के लिए उनकी बहन आयरा खान और उनके पति नुपुर भी मौजूद रहें। इरा, नूपुर, आमिर और जुनैद को एक ही फ्रेम में देखा गया। स्पेशल स्क्रीनिंग में शिरकत करने के लिए दिग्गज अभिनेत्री जूही चावला भी पहुंची। अभिनेत्री आमिर खान के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुकी हैं। इस दौरान एक्ट्रेस ने खुद को मैरून कलर के आउटफिट में स्टाइल किया था। स्क्रीनिंग की शोभा बढ़ाने के लिए साउथ अभिनेत्री प्रियमणि और जान्हवी कपूर भी पहुंचीं। प्रियामणि ने खुद को काफी कैजुअल रखा था और वह तस्वीरें खींचाने से बचती रहीं। वहीं, अपनी बहन को स्पोर्ट करने पहुंची जान्हवी कपूर ने अपनी और खुशी की तस्वीर वाली टॉप पहन रखी थी। जो खुशी के प्रति उनके प्यार को दिखाती है। स्पेशल स्क्रीनिंग का हिस्सा बनने के लिए सिंगर हनी सिंह और अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती भी पहुंचीं। मधु मंटेना और पवन गिल ने भी 'लवयापा' की स्क्रीनिंग का आनंद उठाया।

वॉयस ऑफ कैपिटल
हिन्दी साप्ताहिक समाचार पत्र
स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक एवं सम्पादक सुवर्ण रेखा उपाध्याय द्वारा दीक्षिता ऑफसेट, 105/128 फूलबाग खटियाना, हुसैनगंज, लखनऊ (उ0प्र0) से मुद्रित तथा 71 विज्ञान खण्ड, छोटा भरवारा, चिनहट, लखनऊ, 226028 उ0प्र0 से प्रकाशित।
प्रधान सम्पादक
सुवर्ण रेखा उपाध्याय
मोबाइल नं0
9415074053
RNI. UPHIN/2019/78747
Email
voiceofcapital24@gmail.com
समस्त विवादों का न्याय क्षेत्र लखनऊ न्यायालय ही मान्य होगा